भारत यूएनएससी में जिम्मेदारी लेने को तैयार

सम्मेलन में विभिन्न देशों के सेना प्रमुखों को विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने किया संबोधित

नई दिल्ली 16 अक्टूबर. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र के महत्व पर बल दिया.

उन्होंने कहा है कि यह अफसोस की बात है कि यह संस्था 2025 की वास्तविकताओं के बजाय अभी भी 1945 की वास्तविकताओं को दर्शाती है और इसलिए इसमें सुधारों तथा विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व की जरूरत है. विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी करते हुए कहा कि भारत अधिक जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है. डॉ. जयशंकर ने गुरुवार को यहां संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में

योगदान देने वाले देशों के सम्मेलन में विभिन्न देशों के सेना प्रमुखों को संबोधित करते हुए यह बात कही. विदेश मंत्री ने भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस सम्मेलन के अंतिम दिन अपने विचार रखते हुए कहा कि दुनिया जिन वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है जैसे महामारी से लेकर आतंकवाद तक, और आर्थिक अस्थिरता से लेकर जलवायु परिवर्तन तक – ये चुनौतियां आपस में जुड़ी हुई हैं और राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं.

विकासशील देशों की आवाज बुलंद होना चाहिए

विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रभावी होने के लिए इसमें सुधार होना चाहिए और इसे अधिक समावेशी, लोकतांत्रिक, सहभागी बनना चाहिए. साथ ही इसे आज की दुनिया के अनुरूप बनना चाहिए. इसलिए इसे विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करना चाहिए और उभरते वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए. संयुक्त राष्ट्र की वैधता और विश्वसनीयता, इस पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की इसमें सुधारों की प्रबल इच्छा है जिसमें सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता श्रेणियों का विस्तार भी शामिल है. उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि सुधार की प्रक्रिया का ही उपयोग उस एजेंडे को पटरी से उतारने के लिए किया जा रहा है.

> उन्होंने कहा कि पहला संयुक्त राष्ट्र भी 1945 की वास्तविकताओं को दर्शाता है, 2025 की नहीं. 80 साल किसी भी मानदंड से एक लंबा समय है और इस अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता वास्तव में चौगुनी हो गई है. जो संस्थाएं समय के अनुरूप नहीं ढलने में विफल रहती हैं उनके अप्रासंगिक होने के साथ साथ उनकी वैधता भी कम हो जाती है और वे अनिश्चितता के समय में उस पर निर्भर रहने वालों को बिना किसी सहारे के छोड़ देती हैं.

भगोड़े अपराधियों पर अब जीरो टॉलरेंस

नई दिल्ली 16 अक्टूबर. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में छिपे बैठे भारत के भगोड़े अपराधियों के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी.

उन्होंने कहा भारतीय न्याय व्यवस्था के समक्ष पेशी सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने पर जोर देते हुए राज्यों से भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सहयोग से इन भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने को कहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराध और अपराधी की चाल चाहे कितनी भी तेज हो न्याय की पहुंच उससे भी तेज होनी चाहिए. शाह ने गुरूवार को यहां सीबीआई के भगोड़े अपराधियों के

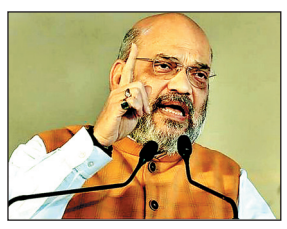

प्रत्यर्पण से संबंधित दो दिन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे कोई भी भगोड़ा अपराधी हो और उसने किसी भी तरह का अपराध किया हो उसे कठोर से कठोर कदम उठाकर भारतीय न्याय व्यवस्था के समक्ष खड़ा करने की जरूरत है. उन्होंने कहा भगोड़े चाहे आर्थिक अपराधी हों, साइबर अपराधी हों, आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हों या संगठित अपराध नेटवर्क के हिस्सेदार हो.

> हर भगोड़े के साथ रुथलेस अप्रोच अपनाकर उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था के समक्ष खड़ा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए. इसका समय आ गया है. उन्होंने राज्यों से भी इसके लिए अपने यहां एक अलग तंत्र बनाने के लिए कहा. उन्होंने कहा, सीबीआई हमारे यहां प्रत्यर्पण के लिए नामित एजेंसी है और सीबीआई के सहयोग से हर राज्य को अपने यहां एक यूनिट खड़ी करनी चाहिए, जो राज्य से भागे हुए भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक तंत्र स्थापित करे. संपूर्ण सरकार अप्रोच से गति भी देनी पड़ेगी.

सड़क योजना ने बदली गांवों की तस्वीर

कृषि मंत्री ने पीएमजीएसवाए योजना की समीक्षा बैठक ली

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने गांवों की तस्वीर और तकदीर बदल दी है यह कहना है ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की.

आगामी कार्य योजना को लेकर अहम निर्देश दिए. ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन, नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश सिंह

सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में मंत्री को राज्यवार प्रगति की जानकारी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते कुछ पहाड़ी और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य धीमा पड़ा है, जबकि अन्य राज्यों में योजना सुचारु रूप से आगे बढ़ रही है. पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर छत्तीसगढ़ में प्रगति को लेकर विशेष चर्चा हुई.

> चौहान ने इन क्षेत्रों में तेज गति से काम करने के निर्देश दिए और बताया कि जल्द ही वे स्वयं एक विशेष क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रतिनिधि व अधिकारी भाग लेंगे. बैठक में यह भी तय किया गया. 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिसंबर 2025 में राष्ट्र व्यापी समारोह आयोजित किए जाएंगे. श्री चौहान ने योजना को ग्रामीण भारत के लिए परिवर्तनकारी पहल बताया और कहा, यह योजना हमारे गांवों की दिशा और दशा दोनों बदलने में सहायक रही है. कृषि मंत्री ने 25 वर्षों की उपलब्धियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए.

जेपी नड्डा से मिले पूर्व पीएम सुनक

'भाजपा को जानें' पहल के तहत गुरुवार को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला. भारत ब्रिटेन संबंधों, स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक के उपयोग और भाजपा के जन आधारित संगठनात्मक ढांचे पर सार्थक चर्चा हुई. समावेशी व विकासोन्मुख शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता साझा की.

आरईसी विद्युत अवसंरचना को वित्तपोषित कर रहा

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर. आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक महारत्न कंपनी है.

आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है. आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं. हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी

विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं. आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है. आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है.

बिहार में एनडीए ने सभी 243 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

पटना, 16 अक्टूबर. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रमुख सहयोगी दलों बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने आगामी दो चरणों वाले बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. सीट बंटवारे के अनुसार, बीजेपी और जदयू 243 सदस्यीय विधानसभा में 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. समझौते के तहत, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों पर, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) छह-छह सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे. मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी. वहीं बिहार चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपनी दूसरी सूची जारी करते हुए सामाजिक समीकरणों को साधने की नई कोशिश की है. पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है. वहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी साधने की रणनीति सामने आई है.

किसानों का दमन कर रही सरकार : अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भाजपा सरकार पर किसानों के खिलाफ दमन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की आवाज उठाने वाले उनकी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है. केजरीवाल ने गुरुवार को एक्स पर एक वीडियो साझा कर कहा कि गुजरात के किसान बेहद दुखी हैं और अपने हक

मांगने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं. पिछले कुछ दिनों से जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. 12 अक्टूबर को बोटाद जिले में किसानों ने दो प्रमुख मांगों पर महापंचायत बुलाई. पहली मांग करदा प्रथा के खिलाफ थी. इस प्रथा के तहत मंडी में किसानों की फसल को खराब बताकर कम दाम पर खरीदते हैं. किसान का अपनी फसल का सही दाम की मांग करना जायज है.